https://www.jmi.c.in

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के शिक्षकों ने राजनीतिक हस्तक्षेप और 'बाहरी लोगों' द्वारा परिसर (कैंपस) को अस्थिर करने की कोशिशों की निंदा की

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2026

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय परिसर को अस्थिर करने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालने और राजनीतिक हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है। शिक्षकों ने राजनीतिक तत्वों द्वारा छात्रों के चल रहे विरोध-प्रदर्शन को और भड़काने तथा एक बड़ा संकट पैदा करने के लगातार प्रयासों पर गहरी नाराजगी जताई है।

यह चिंता कल संकाय डीन, विभागाध्यक्षों, केंद्रों के निदेशकों और विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारियों (जिनमें परीक्षा नियंत्रक, मुख्य प्रॉक्टर, हॉस्टल प्रोवोस्ट और अन्य पदाधिकारी शामिल हैं) की एक बैठक में उठाई गई। यह बैठक परिसर की स्थिति का जायजा लेने, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि की समीक्षा करने और विरोध कर रहे छात्रों की मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू की एक फेसबुक पोस्ट पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया और कड़ी आलोचना की। जस्टिस काटजू ने जेएमआई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को जारी एक आदेश की आलोचना की थी। यह आदेश भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को सौंपे गए मांग-पत्र को स्वीकार करने के संबंध में था। इस आदेश के तहत यह तय किया गया था कि: 1) छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे; 2) विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों के निलंबन और उन्हें जारी किए गए 'कारण बताओ' (शो-कॉज) नोटिस वापस लिए जाएंगे; और 3) विरोध-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। जहां जस्टिस काटजू ने छात्रों के संघ बनाने के अधिकार के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) का हवाला दिया, वहीं शिक्षकों ने उनके इस दावे पर सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। शिक्षकों का कहना है कि यह बात जेएमआई प्रशासन द्वारा 26 अक्टूबर, 2026 को जारी किए गए उक्त आदेश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। शिक्षकों ने बताया कि मौजूदा प्रशासन ने जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (जेएमआईSU) को बहाल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2006 में हिंसक झड़पों और शिक्षकों (जिनमें तत्कालीन कुलपति भी शामिल थे) पर हमलों की लगातार घटनाओं के बाद इस छात्र संघ को भंग कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 20 वर्षों में यह पहला प्रशासन है जिसने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं, जबकि इतने सालों से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

शिक्षकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21 अक्टूबर को एक 'संविधान मसौदा समिति' (draft constitution committee) का गठन किया गया था। इस समिति को अदालती आदेशों, लिंगदोह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों, और विश्वविद्यालय के लागू नियमों व कानूनों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले का राजनीतिकरण करने की राजनीतिक दलों की कोशिशों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के अनधिकृत रूप से परिसर में घुसने के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन को 25 अक्टूबर को FIR दर्ज करानी पड़ी। शिक्षकों के अनुसार, इमरान प्रतापगढ़ी 21 अक्टूबर को गेट नंबर 4A का ताला तोड़कर परिसर में घुसे थे, जबकि इमरान मसूद 23 अक्टूबर को गफूर नगर के पास एक सीढ़ी की मदद से बाउंड्री वॉल फांदकर अंदर आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को भी परिसर आते समय हिरासत में लिए जाने का जिक्र किया, और बताया कि अन्य राजनीतिक नेता भी प्रशासन को पहले से कोई सूचना दिए बिना परिसर में आए थे।

शिक्षकों ने इस बात पर गहरा दुख जताया कि चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच, 'विश्वविद्यालय के बाहर के लोगों' ने 24 अक्टूबर से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों की इमारत पर कब्जा कर लिया है और वहां ताला लगा दिया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति के कारण विश्वविद्यालय को उस तारीख से लेकर दिवाली की छुट्टियों तक पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना पड़ा है, और आगे की स्थिति की समीक्षा के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा।

डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों और उच्च-स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल 'पूर्व छात्रों, जामिया के संस्थापक परिवारों के सदस्यों, कलाकारों, पत्रकारों, वकीलों और अन्य नागरिकों के एक समूह' द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में बुलाई गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय और उसके पीछे के इरादों पर भी सवाल उठाए।

शिक्षकों ने इस बात पर निराशा जताई कि बाहरी ताकतों और लोगों द्वारा विश्वविद्यालय के आंतरिक मामले को एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। यह तब हो रहा है जब प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत करने और उनकी उन मांगों को पूरा करने के लिए 'बेहद सराहनीय प्रयास' किए हैं, जो पिछले 2 दशकों से अनसुलझी पड़ी थीं। यह दोहराते हुए कि विश्वविद्यालय के वास्तविक छात्र और कर्मचारी ही इसके मुख्य और असली हितधारक हैं, शिक्षकों ने बाहरी लोगों से अपील की कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे परिसर का माहौल खराब हो या शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय को अस्थिर करने या इसके सुचारू शैक्षणिक कामकाज में दखल देने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

सीपीआरओ कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया